Year-3 Volume: IV, October-December, 2021 ISSN: 2582-1296
The Asian Thinker
A Quarterly Bilingual Peer-Reviewed Journal for Social Sciences and Humanities

ग्राम पंचायतों तक सरकारी योजनाओं की पहुंच में एम गवर्नेंस की भूमिका

साधिका कुमारी
पीएच.डी. शोधार्थी
माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय, भोपाल
kumarisinghsadhika45@gmail.com

सारांश

भारत का विकास तभी संभव है, जब शहर के साथ-साथ गांवों का भी पूर्ण विकास हो। इसके लिए सबसे जरूरी है कि सरकार से जनता और जनता से सरकार के बीच संवाद का प्रवाह तेजी से हो। ग्रामीण इलाकों को विकास से जोड़ने के लिए आधुनिक संचार साधन की पहुंच ग्राम पंचायतों तक होना जरूरी है। आज दूरसंचार साधन की पहुंच गांव-गांव तक हो चुकी है, खासकर मोबाइल संचार माध्यम से तो अब 80 फीसदी ग्रामीण जनता जुड़ चुकी है। ऐसे में सरकार अपनी पहुंच ग्राम पंचाचतों तक मोबाइल माध्यम से बना रही है। ताकि विकास के कार्यों और उससे जुड़ी जानकारी को जन-जन तक आसानी से पहुंचाया जा सके। सरकार डिजीटल इंडिया के माध्यम से सभी सरकारी योजनाओं की जानकारी अब एक क्लिक यानि मोबाइल एप्लीकेशन पर उपलब्ध करा रही है। ताकि गांव में रहने वाले स्मार्ट मोबाइल फोन उपभोक्ता आसानी से इन योजनाओं की जानकारी हासिल कर सके और विकास की गति को आगे बढ़ाया जा सके। सरकार की जनता तक मोबाइल माध्यम से पहुंच बनाना ही एम-गवर्नेंस है।

की वर्ड- एम गवर्नेंस, ग्राम पंचायत, डिजीटल भारत

प्रस्तावना

महात्मा गांधी ने गांव के विकास से ही देश के विकास की संकल्पना की थी। जो आज सच साबित हो रहा है। देश का विकास तभी संभव है जब शासन से आमजन का संवाद आसानी से स्थापित हो। और गांव-गांव तक सूचना संप्रेषण का प्रवाह तेजी से हो। इसके लिए दूरसंचार माध्यम सबसे ज्यादा प्रभावी साबित हो रहा है। भारत में इंटरनेट उपभोक्ताओं की संख्या भी बढ़ती जा रही है। आज भारत, चीन के बाद विश्व में दूसरा सबसे ज्यादा दूरसंचार उपभोक्ताओं वाला देश बन चुका है। ऐसे में ग्रामीण उपभोक्ताओं में दूरसंचार काफी लोकप्रिय हो चुका है। सितंबर 2019 के ट्राई के आंकड़ों के मुताबिक ग्रामीण भारत में करीब 51 करोड़ दूरसंचार उपभोक्ता हैं। जबकि शहरी भारत में करीब 65 करोड़ उपभोक्ताओं की संख्या है।

"सूचना सामाजिक और आर्थिक गतिविधियों के लिए महत्वपूर्ण है जिसमें विकास प्रक्रिया शामिल होती है। सूचना साझा करने के साधन के रूप में दूरसंचार, लोगों के बीच केवल एक संबंध नहीं है, बल्कि स्वयं विकास प्रक्रिया की श्रृंखला में एक कड़ी है।" [हडसन 1995]

The Asian Thinker

Year-3 Volume: IV, October-December, 2021 ISSN: 2582-1296
The Asian Thinker
A Quarterly Bilingual Peer-Reviewed Journal for Social Sciences and Humanities

मोबाइल ने आज लोगों के काम आसान कर दिया है, चाहे वो ई-कॉमर्स से जुड़ा काम हो या किसी से सीधे संवाद करना हो, अब मोबाइल माध्यम से घंटों का काम मिनटों में होने लगा है। यही वजह है कि अब शासन की योजनाओं को भी मोबाइल माध्यम से संचालित किया जाने लगा है। ताकि आम आदमी तक पहुंच आसान हो सके। मोबाइल माध्यम से शासन करना ही एम-शासन या एम गवर्नेंस है। इससे पहले सरकार की ज्यादातर योजनाएं ई-शासन के माध्यम से संचालित होती थी। जो इंटरनेट और कंप्यूटर के माध्यम से जन-जन तक पहुंचने की कोशिश है। हालांकि मोबाइल माध्यम से शासन के तरीकों में जो बदलाव आया वो ई-शासन का प्रतिस्थापन नहीं बल्कि ई-शासन का पूरक कह सकते हैं। एम-गवर्नेंस मोबाइल तकनीक के जरिए शासन के सेवाओं और सूचनाओं का कहीं भी कभी भी के आधार पर उपलब्ध कराना है। इसकी आसान पहुंच की वजह से ही आज यह दूर-दराज के दुर्गम इलाकों तक सूचनाओं की पहुंच को आसान बना रहा है। यही वजह है कि अब शासन तंत्र अपनी योजनाओं को जन-जन तक पहुंचाने के लिए मोबाइल माध्यम का उपयोग करने लगा है। गांव के विकास के लिए भी यह बेहद जरूरी हो गया है कि शासन तंत्र की हर योजनाओं की खबर ग्रामीणों तक पहुंचे और ग्रामीण जनता को भी अपनी आवाज शासन तक पहुंचाना आसान हो। मोबाइल ही एक ऐसा माध्यम जो सीधे सरकार को जनता से और जनता को सरकार से जोड़ने का काम कर रही है।

शोध के उद्देश्य

1. सरकारी योजनाओं में एम-गवर्नेंस की उपयोगिता को जानना
2. ग्राम पंचायतों तक एम-गवर्नेंस की पहुंच को जानना

शोध प्रविधि

इस शोध को पूरा करने के लिए द्वितीयक आंकड़ों का उपयोग किया गया है। जिसके लिए जरूरी वेबसाइट्स, रिसर्च रिपोर्ट्स और दस्तावेजों से प्राप्त आंकड़ों की व्याख्या की गई है।

मोबाइल गवर्नेंस (M-governance)

सुशासन के लिए सबसे जरूरी सरकारी कामों में पादर्शिता और जनता की भागीदारी का सबसे सशक्त माध्यम आज मोबाइल है। सरकारी विभागों की योजनाओं को मोबाइल के माध्यम से जनता तक पहुंचाना ही मोबाइल गवर्नेंस (एम-गवर्नेंस) है।

मोबाइल-गवर्नेंस के अंतर्गत मोबाइल फोन के जरिए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक सरकारी योजनाओं और उनसे जुड़ी जानकारियों को पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। सूचना एवं संचार क्रांति के इस दौर में प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री, मंत्री, जनप्रतिनिधि मोबाइल माध्यम से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर जनता से जुड़ रहे हैं, ताकि सरकारी सेवाओं की जानकारी आमजन तक आसानी से पहुंचाई जा सके। **इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY),**की बेवसाइट The National Mobile Governance Initiative के मुताबिक भारत में मोबाइल एप के लिए 3,693 एकीकृत विभाग/एजेंसी कार्यरत हैं। जिनके

Year-3 Volume: IV, October-December, 2021 ISSN: 2582-1296
The Asian Thinker
A Quarterly Bilingual Peer-Reviewed Journal for Social Sciences and Humanities

द्वारा सितंबर 2021 तक भेजे पुश एसएमएस की संख्या करीब 41,66,91,48,000 है। वहीं 8,73,61,770 उपभोक्ताओं ने अब तक सरकारी सेवाओं के एप डाउनलोड किए हैं।[1] **सरकार द्वारा संचालित लाइव एप की संख्या 990 है, जबकि कई एप अभी ट्रायल में हैं । विभिन्न भाषाओं में ट्रांसलेट करने वाले एप से लेकर, प्रमुख कानूनी मामलों और प्रक्रियाओं, आधार, कृषि, स्वास्थ्य, भारतीय पोस्ट, भाषा, एम-लर्निंग, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, परिवहन से संबंधित एप मौजूद हैं।**

भारत में इंटरनेट उपभोक्ताओं की संख्या

भारत इंटरनेट उपभोक्ताओं की संख्या के मामले में विश्व में दूसरे स्थान पर है। जबकि भारत में मोबाइल इंटरनेट उपभोक्ताओं की संख्या सबसे अधिक है। साल 2018 तक देश में कुल एक्टिव इंटरनेट उपभोक्ताओं की संख्या 462 मिलियन थी जिसमें मोबाइल इंटरनेट उपभोक्ताओं 430.3 मिलियन थी। [2]

भारत में स्मार्ट फोन उपभोक्ताओं की संख्या

देश में स्मार्टफोन उपभोक्ताओं की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है। सस्ते दर पर उपलब्ध 3जी और 4जी की सेवा दूर-दराज के इलाकों तक सूचना संप्रेषण की बढ़ती चाहत ने स्मार्टफोन उपभोक्ताओं की संख्या में तेजी लाई है। साल 2017 तक जहां 299.24 मिलियन उपभोक्ताओं की संभावित आंकड़े थे वहीं साल 2022 तक यह 442.5 मिलियन पहुंचने की संभावना है। [3]

स्मार्टफोन और इंटरनेट उपभोक्ताओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि आने वाले वक्त में देश की ज्यादातर आबादी केवल स्मार्टफोन के माध्यम से ही इंटरनेट का उपयोग करने वाली है। लोकतांत्रिक प्रणाली में सुशासन स्थापित करने के लिए मोबाइल बेहद जरूरी माध्यम बन गया है। सरकार भी अब मोबाइल के माध्यम से विभागों की योजनाओं को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रही है।

एम-गवर्नेंसऔर नागरिक सुविधाएं

एम-गवर्नेंस सरकारी कामकाजों को मोबाइल माध्यम से जनता तक पहुंचाने का एक साधन मात्र है। यह ई-गवर्नेंस के पूरक के तौर पर कार्य करता है। एम शासन(M-governance) मोबाइल या वायरलेस तकनीक के माध्यम से शासन सेवाओं और सूचनाओं का कहीं भी, कभी भी के आधार पर उपलब्ध कराना है।

[1] https://mgov.gov.in/hindi_mgovhome.jsp
https://apps.mgov.gov.in/index.jsp
[2] https://www.statista.com/statistics/262966/number-of-internet-users-in-selected-countries/
[3] https://www.statista.com/statistics/467163/forecast-of-smartphone-users-in-india/

मोबाइल एप्लीकेशन गुणवत्तापूर्ण सूचना एवं प्रौद्योगिकी आधारित बैक ऑफिस संरचना और कार्यप्रणाली पर आधारित है।

एम-गवर्नेंस के अंतर्गत आने वाली महत्वपूर्ण नागरिक सुविधाएं

- ऑनलाइन बैंकिंग के माध्यम सभी बैंकिंग सेवाओं का लाभ।
- बिजली, पानी, टेलीफोन, मोबाइल, DTH के बिल ऑनलाइन भरने की सुविधा।
- पैन कार्ड, आधार कार्ड, राशन कार्ड, पासपोर्ट, जाती प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र का सत्यापन।
- ऑयकर रिटर्न फाइलिंग के सभी कार्य ऑनलाइन करने की सुविधा।
- ट्रेन, बस और हवाई जहाज की टिकट ऑनलाइन बुक करने की सुविधा।

'मोबाइल फॉर गवर्नेंस इन इंडिया' की रिपोर्ट के मुताबिक63 करोड़ से ज्यादा उपभोक्ताओं तक सुशासन पहुंचाने के लिए मोबाइल तकनीक का बेहतरीन इस्तेमाल किया जा सकता है।'सुशासन और सार्वजनिक सेवाओं के वितरण में मोबाइल प्रौद्योगिकी ने एक परिवर्तनकारी प्रोत्साहक की भूमिका निभाई है। इससे न्यूनतम प्रयासों से ही नागरिकों और सरकार के बीच खुला एवं नियमित संपर्क बना रहता है। सरकारी विभाग एंबुलेंस, अग्निशमन तथा आपात एवं पुलिस सेवाओं से जुड़े अधिकारियों की कार्यकुशलता बढ़ाने में सक्षम हो पाते हैं। लोग सामान्य पूछताछ, सेवा अनुरोध, आपात सहायता, व्यवधान या भ्रष्टाचार की शिकायतों, अपराध, गुमशुदगी और संदिग्ध गतिविधियों की रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए सरकार से सीधे संपर्क कर सकते हैं। देश में फिलहाल चुनाव की निगरानी और सुधार, परियोजनाओं के क्रियान्वयन, यातायात प्रवाह के अनुकूलन, अपराध तथा भ्रष्टाचार रोकने, नागरिकों की भागीदारी बढ़ाने, बिलों के भुगतान, मीडिया को लोकतांत्रिक बनाने और सरकार के साथ जनता का संपर्क बढ़ाने के लिए एम-गवर्नेंस का इस्तेमाल किया जा रहा है।

मोबाइल सेवा सामान्य ई-शासन की बुनियादी सुविधाओं जिसमें राज्य आंकड़ां केंद्र(NDC), राज्य विस्तृत क्षेत्र नेटवर्क (SWAN), राज्य एवं राष्ट्रीय सेवा प्रदायगी गेटवे (SSDG/NSDG) शामिल हैं, को मोबाइल प्लेटफॉर्म के साथ जोड़ने का कार्य करता है। आज भी देश में लाखों लोगों के पास इंटरनेट सेवा नहीं है, जिसकी वजह से वे इंटरनेट आधारित सेवाओं का लाभ नहीं उठा पाते। इसके लिए नागरिकों को ये सेवाएं मोबाइल के विभिन्न संचार माध्यमों जैसे लघु संदेश सेवा (SMS), असंरचित पूरक सेवा डाटा(USSD), इंटरएक्टिव वायस रिस्पॉन्स(IVRS), सेल प्रसारण आधारित सेवाएं(CBS), अवस्थिति आधारित सेवाएं (LBS)के साथ ही स्मार्ट फोन में उपलब्ध मोबाइल

Year-3 Volume: IV, October-December, 2021 ISSN: 2582-1296
The Asian Thinker
A Quarterly Bilingual Peer-Reviewed Journal for Social Sciences and Humanities

एप्लीकेशन(एप) से उपलब्ध कराई जा रही है। मोबाइल आधारित भुगतान गेटवे (Mobile Based Payment Gateway)को मोबाइल सेवा प्रदायगी गेटवे (MSDG) के साथ समन्वित कर दिया गया है ताकि लोग सरकारी सेवाओं के लिए किया जाने वाला भुगतान अपने मोबाइल के माध्यम से कर सकें।[4]मोबाइल तकनीक से आम लोगों के लिए सरकारी सेवाएँ प्राप्त करना आसान हो गया है। मोबाइल-गवर्नेंस का मुख्य उद्देश्य सरकारी विभागों और नागरिकों को एक-दूसरे से परस्पर जोड़ना है।

मोबाइल एप्लीकेशन स्टोर

वर्तमान में नागरिक सेवाओं को मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से सर्वसुलभ बनाने पर जोर दिया जा रहा है। एम-एप स्टोर पर मोबाइल एप्लीकेशन (एम-पासपोर्ट सेवा, एम-रिजर्वेशन, किसान सेवा, हेल्थ आदि) मौजूद हैं, जिनका इस्तेमाल विभागों की योजनाओं का लाभ लेने किया जा सकता है। सरकार द्वारा मोबाइल माध्यम से उपलब्ध कराई जा रही कई महत्वपूर्ण एप्लीकेशन हैं, जिनमें मोबाइल सेवा (Mobile Seva**),** मेड वॉच एप (MedWatch Health App), **एम**-आधार (M-Aadhaar), उमंग (UMANG), भीम (BHIM), स्वच्छता एप (Swachhata App), जनमनरेगा एप, किसान सुविधा (KisanSuvidha), एम-पासपोर्ट सेवा (M-Passport Seva), मेरा अस्पताल एप (MeraAspatal), मेरी सड़क (Meri Sadak), मोबाइल एप्लीकेशन स्टोर (सरकारी सेवाओं हेतु), आरटीआई के लिए एप, ईवीएम की जानकारी प्राप्त करने के लिए एप, एप- इलेक्शन एलिकॉम (मतदान केंद्रों की स्थिति की जानकारी के लिए), भारतीय डाक मोबाइल बैंकिंग एप, एम-परिवहन एप, इनक्रेडिबल इंडिया एप, निर्भया मोबाइल एप, रक्षक एप शामिल हैं।

ग्राम पंचायतों में माबाइल शासन

ग्राम पंचायतों को भी डिजीटल इंडिया से जोड़ा जा रहा है। ग्रामीण इलाकों को भी शहरों की तरह विकसित करने के लिए सरकार लगातार दूर-दराज के गांव को इंटरनेट कनेक्शन से जोड़ रही है। और मोबाइल के बढ़ते प्रचलन ने सरकार की जनता तक पहुंच को और आसान बना दिया है। डिजीटल इंडिया के तहत केंद्र सरकार ने ग्रामीण इलाकों में मोबाइल फोन उपभोक्ताओं को जानने के लिए एक सर्वे कराया, जिसमें पता चला कि देशभर में करीब 80 फीसदी ग्रामीण जनता स्मार्ट फोन उपभोक्ता है। केंद्र सरकार ने अपनी योजनाओं की जानकारी ग्रामीणों तक पहुंचाने के लिए ग्राम संवाद नामक एप लॉन्च किया है। एप के माध्यम से ग्रामीण सरकार द्वारा गांवों के लिए संचालित सभी योजनाओ की पूर्ण जानकारी ले सकते हैं।

[4]https://www.india.gov.in/hi/spotlight/मोबाइल-सेवा-मोबाइल-फ़ोन-के-माध्यम-से-नागरिकों-को-उपलब्ध-करवाई-जाने-वाली-सेवाएँ

Year-3 Volume: IV, October-December, 2021 ISSN: 2582-1296
The Asian Thinker
A Quarterly Bilingual Peer-Reviewed Journal for Social Sciences and Humanities

इसके लिए ग्राम संवाद एप अपने मोबाइल में डाउनलोड करना होगा। देश के दूर-दराज इलाकों में बसे गांव आज भी मूलभूत सुविधाओं जैसे शिक्षा, चिकित्सा, सड़क, बिजली, पेयजल आदि से वंचित हैं। इसके साथ ही अधूरी जानकारी की वजह से ग्रामीण सरकार की योजनाओं का लाभ नहीं उठा पाते। ऐसे में डिजीटल इंडिया के तहत ग्राम संवाद और ग्राम पंचायत एप उन ग्रामीणों की मुश्किलों को हल कर रहा है। इन एप्स पर गांवों के लिए जारी विकास की धनराशि के खर्च के साथ सभी योजनाओं की प्रगति का ब्योरा भी उपलब्ध है।

ग्राम पंचायतों के लिए मोबाइल एप्लीकेशन

गांव को सीधे सरकार से जोड़ने के लिए की मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किए गए है। ई-ग्राम स्वराज, ग्राम संवाद, पंचायत दर्पण, जनमनरेगा, कृषि किसान, जनसुनवाई आदि मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से ग्रामीण जनता अब सीधे सरकार से संवाद कर सकती है। और क्षेत्र में हो रहे विकास कार्यों की जानकारी प्राप्त कर सकती है।

गांव में मोबाइल शासन की आवश्यकता

तेजी से भारतीयों के बीच अपना स्थान बनाते, मोबाइल भारत में विभिन्न ई-शासन सेवाओं की एक वितरण चैनल के रूप में उभरा है। स्वीकृति में सरलता और साधारण इंटरफेस एप्पस को डाउनलोड करने में स्वतंत्रता और इसे आसान तरीके से उपयोग करने के लिए उपयोगकर्ता को अवसर देता है। हालांकि अभी भी प्रौद्योगिकी के मोर्चे पर एप्लीकेशन्स को लोगों तक पहुँचाने की चुनौतियां हैं। विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में मोबाइल अनुप्रयोगों की संभावितों तक पहुंच में सबसे बड़ी चुनौती है। इस बिंदु को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने इस समस्या के समाधान के लिए अनेक कदम उठाएं हैं और इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभान ने सभी विभागों और एजेंसियों को मोबाइल एप्लीकेशन का विकास करने और लोगों तक इसकी पहुँच बनाने के लिए अनेक योजनाओं की घोषणा की है। विभाग द्वारा निर्धारित मुख्य उपाय इस प्रकार हैं:

- सभी सरकारी विभागों और एजेंसियों की वेब साइटों को निर्देशित किया गया है कि "वन वेब" दृष्टिकोण के अंतर्गत मोबाइल-कंप्लाइंट का विकास किया जाए।
- मोबाइल एप्लीकेशन के लिए ओपन मानकों को अपनाया जाए ताकि ई-शासन के अंतर्गत लागू की जा रही शासन की नीति के अनुसार एप्लीकेशन के अनुसार विभिन्न ऑपरेटिंग सिस्टम और उपकरणों में पारस्परिकता बनी रहे।
- यूनीफार्म/सिंगल पूर्व- नामित संख्या (लंबी और शॉर्ट कोड) का उपयोग मोबाइल आधारित सेवाओं के लिए करके दी जा रही सुविधा को सुनिश्चित किया जा सके।

- सभी सरकारी विभागों और एजेंसियों द्वारा दी जा रही सार्वजनिक सेवाएं को मोबाइल उपकरणों के माध्यम से प्रदान करने से लेकर विकसित एप्लीकेशन को मोबाइल प्लेटफार्म के अनुकूल बनाना होगा।

मोबाइल सेवा एक एकीकृत प्लेटफार्म प्रदान करती है जिसके सहायता से नागरिकों को सार्वजनिक सूचना और सरकारी सेवाओं का वितरण, मोबाइल उपकरणों पर एसएमएस, यूएसएसडी, आईवीआरएस, सीबीएस, एलबीएस या मोबाइल फोन पर स्थापित मोबाइल अनुप्रयोगों के द्वारा किया जा सकता है।

शोध का निष्कर्ष

मोबाइल प्रौद्योगिकी के तेजी होते विकास के साथ ही ग्रामीण जनता तक इसकी आसान पहुंच ने विकास कार्यों को आसान बनाया है। अब आसानी से दूर दराज के गांव तक सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचाई जा रही है। और ग्रामीण जनता भी विकास से जुड़ी योजनाओं को लाभ उठा रही है। यही नहीं ग्राम पंचायतों के लिए जारी धनराशि का व्यौरा भी मोबाइल एप्लीकेशन पर उपलब्ध है, जिसके माध्यम से ग्रामीण जनता ग्राम पंचायत स्तर पर हो रहे विकास कार्यों की जानकारी हासिल कर सकते हैं। और इसमें धांधली के शक होने पर अपनी आवाज उठा सकते हैं। वहीं एम गवर्नेंस के माध्यम से गांवों के विकास के लिए कृषि, हेल्थ, रोजगार से जुड़ी जानकारी के लिए एप्लीकेशन मौजूद हैं। साथ ही ग्रामीण जनता को सहायता उपलब्ध कराने के लिए एप्लीकेशन में संवाद की व्यवस्था की भी गई है। इस सुविधाओं के आधार पर यह कहा जा सकता है किअब सूचना प्रौद्योगिकी के विकास के साथ गांव का विकास भी संभव हो गया है।

संदर्भ सूची

1. Countries with the highest number of internet users as of December 2017. (2017). Retrieved Oct 22, 2018, from The Statistics Portal: https://www.statista.com/statistics/262966/number-of-internet-users-in-selected-countries/
2. Debora, M. (February 2018). M-Governance in India: Issues and Initiatives. International Journal of Computer & Mathematical Sciences , 198-203.
3. Digital population in India as of January 2018. (2018). Retrieved Oct 22, 2018, from The Statistics Portal: https://www.statista.com/statistics/309866/india-digital-population/

The Asian Thinker

4. Kulkarni-Bhende, S. C. (2015). Mobile Enabled Governance For Local Government In India. Indian Journal of Computer Science and Engineering , 114-123.

5. Number of smartphone users in India from 2015 to 2022. (2018). Retrieved Oct 22, 2018, from The Statistics Portal: https://www.statista.com/statistics/467163/forecast-of-smartphone-users-in-india/

6. Ranawat, A. J. (2017). M-Governance in India:Problems and Acceptability. Imperial Journal of Interdisciplinary Research (IJIR) , 1565-1570.

7. Urban Development & Housing Department Government of Bihar. (n.d.). Retrieved Oct 22, 2018, from nagarseva.bihar.gov.in: https://nagarseva.bihar.gov.in/udhd/Home.html

8. Vaishali Kadu, V. M. (2015). Transforming from e-Governance to M-Governance . International Journal of Advanced Research in Computer and Communication Engineering , 457-462.

9. Vinay Kumar, P. P. (2015). Mobile Apps in E-Governance Projects in India: Where Do We Stand. International Journal of Sciences: Basic and Applied Research , 392-397.

10. अब आ गया एम-गवर्नेंस का जमाना. (2018, June). Retrieved Oct 22, 2018, from आउटलुक:https://www.outlookhindi.com/business-and-economy/policies/now-it-is-m-governance-era-2525

11. मोबाइल सेवा. (n.d.). Retrieved Oct 22, 2018, from india.gov.in: https://www.india.gov.in/hi/spotlight/मोबाइल-सेवा-मोबाइल-फ़ोन-के-माध्यम-से-नागरिकों-को-उपलब्ध-करवाई-जाने-वाली-सेवाएँ

12. CHANDEL, S. (2018, FEBRUARY 14). GOAN CONNECTION. Retrieved from इस ऐप के जरिए एक क्लिक पर मिलेगी ग्रामीण योजनाओं की जानकारी : https://www.gaonconnection.com/desh/information-on-rural-schemes-will-be-available-on-one-click-through-this-app?infinitescroll=1

13. AMAR UJALA. (2020, MARCH 13). Retrieved from ट्राई की रिपोर्ट : भारत में वयस्क आबादी से ज्यादा हैं मोबाइल फोन: https://www.amarujala.com/india-news/trai-report-says-there-are-more-number-of-mobiles-than-adult-population-in-india

The Asian Thinker